



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 2 जनवरी, 2009 / 12 पौष, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 1 जनवरी, 2009

संख्या ई०एक्स०एन०-एफ(5)-4 / 2006.—हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्याक 12) से संलग्न अनुसूची "क" के भाग-2 में संशोधन हेतु प्रारूप को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसरण में इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं० ई०एक्स०एन०-एफ(5)-4 / 2006 तारीख 3-10-2008 द्वारा, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 6-10-2008 में प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के भीतर इस बाबत कुछ आक्षेप/सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन्हें विचार करने के उपरान्त, अस्वीकृत कर दिया गया है ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्याक 12) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची "क" (जिसे इसमें इसके पश्चात "उक्त अनुसूची" कहा गया है) के भाग-2 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्याक 12) से संलग्न अनुसूची "क" के भाग-2 में विद्यमान मद संख्या-2 के पश्चात् निम्नलिखित मद 2-क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"2-क सुगरकेन बगासे और अन्य कृषि अपशिष्ट से निर्मित काष्ठमुक्त एग्रोबोर्ड तथा पार्टिकल बोर्ड ।"

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव।

(Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(5)-4/2006, dated 01-01-2009 required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.)

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 1st December, 2009

File No. EXN- F(5)-4/2006.—Whereas the draft amendment in Part-II of Schedule-A appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005) issued by the government vide notification No. EXNF(5)-4/2006 dated 3-10-2008 published in Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 06-10-2008 in pursuance of the provisions of section 10 of the aforesaid Act for inviting objections and suggestions from the person(s) likely to be affected thereby.

And whereas some objections/suggestions have been received within stipulated period in this behalf which have been considered and rejected.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 10 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in Part-II of Schedule-A appended to the aforesaid Act (hereinafter called the said Schedule) namely:-

AMENDMENTS

In PART-II of the Schedule 'A', appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), after existing item No. 2, the following item 2-A shall be inserted, namely:-

"2-A. Wood free Agro Boards and Particle boards made from Sugarcane bagasse and other agri-residue. ”.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग**अधिसूचनाएं**

शिमला-171002, 26 दिसम्बर, 2008

संख्या सिंचाई 11-61/2008-कांगड़ा.-यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव लखवाल, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा में जल भण्डार लखवाल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र हैक्टेयरों में
कांगड़ा	नूरपुर	लखवाल	268/1 किता-1	0.01.00 0.01.00

शिमला-171002, 26 दिसम्बर, 2008

संख्या सिंचाई 11-44/2008-कांगड़ा.-यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु पेयजल योजना रामनगर-श्यामनगर के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र (वर्गमीटर में)
कांगड़ा	धर्मशाला	महाल, श्यामनगर	548/1	119-25 वर्गमीटर

शिमला-171002, 26 दिसम्बर, 2008

संख्या सिंचाई 11-67/2008-कांगड़ा—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल पनियाला, मौजा मन्दोली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में शाहनहर परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	महाल व मौजा	खसरा नं०	क्षेत्र हैक्टेयरों में
कांगड़ा	इन्दौरा	पनियाला / मन्दोली	677/1/2	0-01-87
			673/2	0-04-67
			677/1	0-00-22
			678/1	0-00-15
			1256/1	0-00-12
			1256/2	0-00-28
			1259	0-01-56
			1265/2	0-15-07
			1265/3	0-34-73
			1292	0-14-26
			1293	0-09-48
			1299	0-00-30
			किता-12	0-83-03 है०

शिमला-171002, 26 दिसम्बर, 2008

संख्या सिंचाई 11-62/2008-कांगड़ा—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः गांव वगोड़ा, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा में पेयजल योजना कण्डी भगोटला फेश नं० 2 के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन समाहर्ता, भू-अर्जन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, जिला कांगड़ा को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक, समाहर्ता, भू-अर्जन लोक निर्माण कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र हैक्टेयरों में
कांगड़ा	पालमपुर	वगोड़ा	42/1	0-00-25 है०

शिमला-171002, 22 दिसम्बर, 2008.

संख्या: सिंचाई 11-66/2008-कांगड़ा.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल करडयाल, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में सिद्धांश माध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	महाल	खसरा न०	क्षेत्र/हैक्टेयर में
कांगड़ा	ज्वाली	करडयाल	560/1	0-06-00
			561/1	0-02-00
			562/1	0-01-84
			570/1	0-03-22
			564/1	0-06-83
			565/1	0-03-04
			567/1	0-01-90
			569/1	0-05-38
			528/1	0-07-49
			529/1	0-02-00
			531	0-00-98
			532/1	0-06-86
			618/1	0-02-52

			1095/621/1	0-08-32
			479/1	0-05-50
			1072/636/1	0-06-05
			652/1	0-06-30
			513	0-00-42
			514	0-02-20
			515	0-02-97
			536/1	0-04-93
			542/1	0-02-00
			553/1	0-01-88
			556/1	0-02-16
			537/1	0-10-02
			538/1	0-00-82
			566	0-04-03
			763/1	0-02-80
			208/1	0-01-98
			212/1	0-02-73
			385/1	0-00-32
			386/1	0-00-40
			384/1	0-00-85
			387/1	0-04-13
			388/1	0-02-72
			391/1	0-03-91
			392/1	0-04-14
			393/1	0-01-95
			399/1	0-03-12
			496/1	0-06-68
			690/1	0-08-29
			652/1	0-03-89
			654/1	0-03-13
			648/1	0-03-78
			211/1	0-04-87
			765/1	0-05-05
			641/1	0-04-16
			701/1	0-07-26
			963/1	0-02-21
			907/1	0-02-87
			961/1	0-04-48
			628/1	0-02-00
			680/1	0-07-52
			647	0-04-10
			646	0-03-10
			711	0-03-63
			712	0-02-64
			713	0-03-49
			673/1	0-04-90
			965/1	0-08-38

			906/1	0-02-17
			669/1	0-02-88
			894/1	0-03-00
			900/1	0-02-87
			903/1	0-01-75
			877/1	0-03-75
			714/1	0-10-00
			855/1	0-02-80
			876/1	0-02-38
			748/1	0-01-48
			749/1	0-01-51
			858/1	0-01-80
			859/1	0-03-22
			742/1	0-03-32
			किता-74	2-76-07 है0

शिमला-171002, 26 दिसम्बर, 2008

संख्या सिंचाई 11-43/2008-शिमला—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः वड़गांव, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला में (भैरा खड्ड से सरोगा) उठाऊ पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघा/बिस्वा में
शिमला	कुमारसैन	बड़गांव	591/1 839/1 किता-2	0-09-31 0-05-18 0-14-49

शिमला-171002, 26 दिसम्बर, 2008

संख्या सिंचाई 11-62/2008-कुल्लू—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः फाटी दियार कोठी काटे कण्डी

तहसील व जिला कुल्लू में पम्प हाऊस उठाऊ पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, मण्डी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	क्षेत्र बीघा/बिस्वा में
कुल्लू	कुल्लू	भेड़फार्म	2911 2725 <u>2793</u> किता-3	0-01 0-13 <u>0-03</u> 0-17

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव ।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 20 दिसम्बर, 2008

संख्या-पीसीएच-एचबी(2)9/99-37089-204.-हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 16-4-2007 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग, लिपिक (वर्ग-111, अराजपत्रित) पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज विभाग लिपिक,(वर्ग-111, अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये नियम राजपत्र,हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

उपाबन्ध 'क' का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग, लिपिक (वर्ग-111 अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबन्ध 'क' में,

(क) स्तम्भ संख्या 7(1) के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या इसके समतुल्य”

(ख) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

वर्ग IV कर्मचारियों में से, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या इसके समतुल्य और जिनका 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा:

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानांतरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I :- उपर्युक्त परन्तुक 1 के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में “कार्यकाल” से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II :- उपर्युक्त परन्तुक 1 के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे:-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगडा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरु के काठवाड और कोरगा परवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्थोल-बगडा पटवार वृत्त, बालीचौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठकानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड, कुटगढ, ग्रामन, देवगड, टैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेड पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ, थाच-बगडा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत्त।

परन्तु वर्ग IV के पात्र व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन सोसायटी के माध्यम से कार्यालय प्रक्रिया, टंकण और वर्ड प्रोसेसिंग में 2 मास का प्रशिक्षण या तो संस्थान में या उनके अपने-अपने जिला प्रशिक्षण केन्द्रों में दिया जाएगा। प्रशिक्षित अभ्यर्थी प्रोन्नति के लिए पात्र होगा। प्रशिक्षण केवल एक बार दिया जाएगा, किन्तु जो परीक्षा को एक बार में उत्तीर्ण करने में असमर्थ रहते हैं उनको समय समय परीक्षा में बैठने हेतु अवसर दिया जाएगा :

परन्तु वर्ग IV के पदों के पदधारियों को, जो इस प्रकार प्रोन्नत हुए हैं या करुणामूलक आधार पर नियुक्त हुए हैं जिनकी शैक्षणिक अर्हता तृतीय श्रेणी में मैट्रिक पास या ऐसी नियुक्ति के समय हिन्दी स्तन मैट्रिक के अंग्रेजी के विषय सहित पास हो, "वरिष्ठ सहायक" के पद पर तब तक प्रोन्नति के विचार के लिए पात्र नहीं समझा जायेगा जब तक कि वे सीधी भर्ती के लिए उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7 में विहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं प्राप्त नहीं कर लेते।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र वर्ग IV कर्मचारियों की उनकी काडर वार पारस्परिक वरीयता को छोड़े बिना एक संयुक्त वरीयता(वरिष्ठता) सूची तैयार की जाएगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी;

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण:— अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

[Authoritative English text of this Department Notification No.PCH-HB(2)9/99-37089-204 dated 20.12.2008 as required under clausd 348(3) of the Constitution of India].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-9, 20th December, 2008

No.PCH-HB(2)9/99-37089-204.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased further to amend the Himachal Pradesh

Panchayati Raj Department, Clerk(Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007, notified vide notification of even number dated 16.4.2007, namely

1. Short title and commencement.— (1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj Department Clerk, (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2008.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A to the Himachal Pradesh Panchayati Raj Department, Clerk(Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007, the following shall be substituted, namely:-

(a) For the existing provision against column No. 7(i) the following shall be substituted namely:-

“Should have passed 10+2 examination or its equivalent from a recognized University/ Board.”

(b) For the existing provision against column No. 11 the following shall be substituted namely:-

By promotion from amongst the Class-IV who have passed 10+2 or its equivalent from a recognized University/Board and also possess 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any, in the grade.

Provided further that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/ Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas;

Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/ her seniority in the respective cadre.

Explanation I :- For the purpose of proviso I supra the “term” in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II:-For the purpose of proviso I supra the Tribal/ Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmaur Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhargal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar circle of Renukaji Tehsil and Kota Pab patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmaur District .
9. Khanyol-Bagra patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kohlanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Traila, Ropa, kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Provided that the 2 months training to the eligible Class-IV persons will be given in office procedure, typewriting and word processing through HIPA Society either at the Institute or at their respective District Training Centers. Trained candidate will be eligible for promotion. Training will be held only once but opportunity for appearing in the test will be given from time to time to those who are unable to pass the test in one go.

Provided further that the incumbents of the posts of class-IV officials so promoted or appointed on compassionate grounds having the educational Qualification of Matric pass in 3rd division or Matric(English) only and Hindi Rattan pass at the time of such appointment, shall not be considered to be eligible for their promotion for the posts of Senior Assistant until they possess the minimum educational qualifications prescribed for direct recruitment as prescribed in Column No. 7 above.

For the purpose of promotion a combined seniority of eligible Class-IV officials on the basis of their length of service without disturbing their cadre-wise inter-se-seniority shall be prepared.

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules, provided that,

that in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis , followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R & P Rules for the post whichever is less;

Provided further that where a person become ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel(Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules ,1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of

Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the Recruitment and Promotion rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged”.

By order,
Sd/-
Special Secretary.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th December, 2008

No. UD-A(1)-2/2006-Bilaspur.—In exercise of the powers vested in him under Sub-Section (2) of Section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) read with sub-rule (6) of rule 7, rule 8 and rule 9 of the Himachal Pradesh Municipal (Reservation and Election to the office of President/Vice President) Rules, 1995, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the official gazette the election of President/ Vice-President in respect of Municipal Council Bilaspur as under:-

Name & Address of Elected President	Name & Address of Elected Vice-President
Sh. Ashish Dhillo S/o Sh. Munshi Ram R/o ward No. 11 Lakhanpur, Teh. Sadar, Distt. Bilaspur.	Sh. Kanhya Lal Surehli S/o Sh. Chajju Ram , Ward No. 6 Kosrain, Teh. Sadar, Distt. Bilaspur.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

